उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
कार्यालय ज्ञाप/अधिसूचना

27 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 570/XII(1)-2022-86(05)/2022–राज्यपाल, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच (contemporaneous rigorous empirical inquiry) हेतु श्री बी0एस0 वर्मा, सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग (Dedicated Commission) गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त आयोग निम्नलिखित Terms of Reference के आधार पर अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसायें राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी:–

(i) राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच (contemporaneous rigorous empirical inquiry) करना।

(ii) अभिलेखों, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों एवं अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या के सापेक्ष ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायवार अन्य पिछडे वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात का विनिश्चय करना तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–356/1994 के0 कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार में दिनांक 11.05.2010, रिट पिटीशन संख्या–980/2019 विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04 मार्च 2021 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या–278/2022 सुरेश महाजन बनाम् मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनांक 10.05.2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में राज्य सरकार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

(iii) आयोग अपनी अनुशंसा/संस्तुति आयोग के गठन की तिथि से 01 वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की गयी अन्य अवधि के भीतर उपलब्ध करायेगा।

(iv) उपरोक्त एकल सदस्यीय आयोग में सचिवीय सहायतार्थ (Secretarial Assistance) यथा कार्यालय स्टाफ/वाहन आदि पर होने वाला व्यय निदेशक, पंचायती राज देहरादून के प्रशासकीय मद से वहन किया जायेगा।

(v) उपरोक्त आयोग के सदस्य सचिव के रूप में श्री ओमकार सिंह, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन कार्य करेंगे।

(vi) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.10.1987 के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जांच आयोगों/समितियों में नियुक्त होने पर उनके वेतन नियतन तथा अन्य शर्तों के सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं समय समय पर संशोधित आदेशों तथा तत्क्रम में मंत्रिपरिषद अनुभाग(गोपन विभाग), उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के क्रम में मा0 आयोग को सभी सुविधायें अनुमन्य होंगी।

3. आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने हेतु :–

(a) विभिन्न संगठनों / संस्थाओं / व्यक्तियों / विभागों से ऐसी सूचना अथवा आंकडे, जो भी इस हेतु आवश्यक हो अथवा प्रासंगिक हो, की मांग एवं सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

(b) विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ बैठकें आहूत करके उनकी सलाह ले सकेगा और जब भी आवश्यक हो, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं से अनुभवजन्य आंकडों के विश्लेषण और आयोग के कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(c) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य या भारत के अन्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे हेतु अध्ययन भ्रमण का प्रबन्ध कर सकेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.570/XII(1)-2022-86(05)2022 Dehradun, Dated: July 27, 2022 for general information.

OFFICE MEMORANDUM/ NOTIFICATION

July 27, 2022

No.570/XII(1)-2022-86(05)/2022–In compliance of the order passed on dated 10.05.2022 by the hon'ble Supreme Court of India in connection with the writ petition (Civil) no. 278/2022 Suresh Mahajan Vs State of Madhya Pradesh and Others, dated 10th May, 2022, the Governor is pleased to allow to constitute a single member dedicated commission under the Chairmanship of Sri B.S. Verma, Retd. Hon'ble Judge, Hon'ble High Court Uttarakhand, Nainital to conduct contemporaneous rigorous empirical enquiry into the nature and implications of the backwardness of others backward class within the State under every local bodies.

2. The aforesaid Commission on the basis of following terms of reference shall submit its reports and recommendations to the State Government.

(i) To conduct the contemporaneous rigorous empirical enquiry into the nature and implications of the political backwardness of Other Backward Classes in the every local bodies within the State.

(ii) To submit report to the State Government in the light of judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in the writ petition no. 356/1994 k. Krishna Murthy Vs Union of India, writ petition no. 980/2019 Vikas Kishan Rao Gawali Vs State of Maharastra and ors. and writ petition (Civil) no. 278/2022 Suresh Mahajan Vs State of Madhya Pradesh and Ors. on dated 11.05.2010, 04.03.2021 and 10.05.2022 respectively and to ascertain rural and urban local body-wise proportion of population of Other Backward Class of citizens to the total population on the basis of records, reports, surveys and other available data.

(iii) The Commission submit its suggestions/recommendations to the State Government within the period of one year from the date of its constitution such period as may be other wise extended by the State Government.

(iv) The expenditure occurred on the Secretarial Assistance as office Staff/vehicle etc. shall be borne from the administrative item of the Director, Panchayat Raj Dehradun in the aforesaid single member Dedicated Commission.

(v) Sri Omkar Singh, Additional Secretary, Department of Panchayat Raj, Government of Uttarakhand shall be Member Secretary of the aforesaid Commission.

(vi) The all facilities are admissible to the Hon'ble Commission in continuation of issued guiding principles regarding the pay fixation and other conditions on their appointment in the enquiry Commissions/Committees of retired Judges of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts by the office memorandum dated 8th October, 1987 of the Ministry of Finance Government of India and amended orders from time to time and in continuation of issued orders from time to time by the Cabinet Section (Gopan Department) Government of Uttarakhand.

3. For preparing its report by the Commission:-

(a) obtaining such information or data, as it may consider necessary or expedient for this purpose and take the assistance from the various organizations/ institutions/ individual/ departments.

(b) avail advice of experts and researchers by holding meetings with them and also get assistance recognized research institutions as and when necessary for analysis of the empirical data and also the efficient and effective functioning of the Commission.

(c) arrange study tours to visit the various areas in the State of Uttarakhand or in other States of India to achieve the above objectives.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 19–11–2022, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 पंचायती राज/747–18–12–2022–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।